DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण नई दिल्ली, 9 फ़रवरी, 2024

डीडीए के बजट में ढांचागत परियोजनाओं पर रहेगा जोर

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: डीडीए के बजट में इस बार मुख्य फोकस दिल्ली के ढांचागत विकास पर होगा। दैनिक जागरण ने चार फरवरी के अंक में ही 'बजट में रहेगा ढांचागत विकास पर जोर' शीर्षक से प्रकाशित खबर में इस आशय की जानकारी साझा कर दी थी। इसमें बताया था कि इस बार वजट में दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान, तीसरी रिंग रोड यानी यूईआर टू व जहां झुग्गी वहीं मकान जैसी योजनाएं प्रमुखता से शामिल रहेंगी।

1-परिवहन

• 6421 करोड़ रूपये की लागत वाले यूईआर-दो (केवल दिल्ली का हिस्सा) का निर्माण कार्य जल्द ही पूर्ण होने वाला है। कार्य को गति देते हुए वर्ष 2023-24 के आवंटन को 920 करोड़ रुपये से 1590 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है। परियोजना को पूरा करने के लिए बजट अनुमान 2024-25 में 400 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है।

• दिल्ली मेट्रो परियोजना फेज-4 के लिए वर्ष 2023-24 में आवंटन को 350 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 390 करोड़ तक कर दिया गया है। बजट अनुमान 2024-25 में 275 करोड़ का प्रविधान किया गया है।

• मैदानगढ़ी मे एसएएआरसी विश्वविद्यालय सीएपीएफआईएमएस (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान) को छतरपुर रोड से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण प्राथमिकता आधार पर किया जा रहा है। 2024-25 के बजट अनुमान और वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान मे क्रमशः 100 करोड़ और 20 करोड़ का प्रविधान किया गया है।

• नेहरु प्लेस एवं भीकाजी कामा प्लेस में दो मल्टीलेवल कार पार्किंग निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त नेताजी सुभाष प्लेस में एक अन्य मल्टीलेवल कार पार्किंग प्रस्तावित है। बजट अनुमान 2024-25 में 70 करोड़ रुपये का प्रविधान है।

3-स्टार्म वाटर चैनल

किरारी स्टार्म वाटर चैनल, द्वारका में स्टार्म वाटर चैनल संख्या दो व पांच, द्वारका सेक्टर आठ में स्टार्म वाटर ड्रेन, रानी खेड़ा से सेक्टर 40, रोहिणी तक स्टार्म वाटर ड्रेन। बजट अनुमान 2024-25 और संशोधित अनुमान 2023-24 में क्रमशः 165 करोड़ और 267 करोड़ का समग्र प्रविधान किया गया है। इससे यमुना के प्रदूषण, जल जमाव/बाद, भूजल को दूषित होने से रोकने में मदद मिलेगी। यह नालों और जलाशयों का निर्माण करके पार्कों की सिचाई की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

बैठक करते अधिकारी • जागरण आर्काइव

बजट में व्यय प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं

क) नागरिक आधारिक संरचना का विकास, 3460 करोड़ का आवंटन

भूमि और भौतिक आधारिक संरचना के विकास के लिए कुल 3460 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें नरेला, द्वारका, रोहिणी उपनगरों व अन्य क्षेत्रों के खाली हिस्से में सड़कें, सीवेज, जलापूर्ति, बिजली लाइनें और जल निकासी सौंदर्यीकरण, सौंदर्य उन्नयन और सड़कों का निर्माण शामिल है।

2-दिल्ली ग्रामोदय अभियान

दिसंबर 2023 में लांच दिल्ली ग्रामोदय अभियान के लिए बजट अनुमान 2024-25 और संशोधित अनुमान 2023-24 में क्रमशः 600 करोड़ और 300 करोड़ का प्रविधान किया गया है।

बजट में रहेगा ढांचागत विकास पर जोर

दैनिक जागरण में चार फरवरी के अंक मे प्रकाशित की गई खबर •

4. स्वच्छ और हरित दिल्ली के लिए पहल

• आइटीओ ब्रिज के पास असिता ईस्ट, सराय काले खां बस डिपो के पास बासेरा और आइएसबीटी, कश्मीरी गेट के पास वासुदेव घाट सहित दिल्लीवासियों के लिए रिवरफ्रंट पर विशिष्ट स्थानों का निर्माण किया जा रहा है। बजट अनुमान 2024-25 और संशोधित अनुमान 2023-24 में क्रमशः 142 करोड़ और 96 करोड़ का प्रविधान किया गया है।

• सेक्टर 20, द्वारका में भारत वंदना पार्क का निर्माण। बजट अनुमान 2024-25 मे 150 करोड़ का और वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान में क्रमशः 200 करोड़ का प्रविधान है।

• बायोडायवर्सिटी पार्कों का विकास और रखरखाव। बजट अनुमान 2024-25 में 66 करोड़ और वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान में 40 करोड़ का प्रविधान किया गया है।

• हरित स्थानों का समग्र विकास और आधुनिकीकरण। वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में 65 करोड़ और वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान में 61 करोड़ का प्रविधान किया गया है।

• एसटीपी पाइपलाइन के माध्यम से जलाशयों का कायाकल्प और शोधित जल का उपयोग। बजट अनुमान वर्ष 2024-25 में 45 करोड़ और वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान में 28 करोड़ का प्रविधान किया गया है।

• राजघाट पावर प्लांट को एक शैक्षिक सार्वजनिक स्थल में परिवर्तित करना

और मौजूदा चिमनी को फसाड/इल्युमिनेशन लाइटिंग और लेजर शो के माध्यम से विशेष रूप से दर्शाना। बजट अनुमान 2024-25 में दो करोड़ का प्रविधान किया गया है।

• लाल किले के पीछे चार पार्कों का पुनर्विकास। बजट अनुमान 2024-25 और संशोधित अनुमान 2023-24 में 37 करोड़ एवं .50 करोड़ का प्रविधान ।

(ख) स्वस्थ और फिट दिल्ली के लिए खेलों को बढ़ावा देना

• द्वारका में तीन नए खेल परिसरों, रोहिणी में एक खेल परिसर का और द्वारका में एक गोल्फ कोर्स का निर्माण हो रहा है। नरेला के लिए खेल परिसर का प्रस्ताव किया जा रहा है। 2024-25 और 2023-24 के अनुमान में क्रमशः 266 करोड़ व 196 करोड़ का प्रविधान।

(ग) आवास परियोजनाएं और इन-सीटू स्लम पुनर्वास

• आवास परियोजनाओं के लिए वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान में 1953 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।

• कड़कड़डूमा, दिल्ली में ट्रांजिट ओरिएंटिड डेवलपमेंट (टीओडी) परियोजना के लिए वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान और वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान में क्रमशः 450 करोड़ और 245 करोड़ का प्रविधान है।

• विभिन्न क्षेत्रों में इन-सीटू स्लम पुनर्विकास/पुनर्वास के माध्यम से स्लम वासियों को पक्के मकान उपलब्ध कराना। 2024-25 के बजट अनुमान और वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान मे क्रमशः 62 करोड़ और 98 करोड़ का प्रविधान किया गया है।

अनधिकृत निर्माण रोकने में अफसर विफल, ध्वस्त हो जाएगी व्यवस्था

• याचिका में निजामुद्दीन दरगाह में अवैध और अनधिकृत निर्माण की शिकायत की गई है

• हाई कोर्ट ने कहा, सीबीआइ को जांच सौंपी तो पुलिस की भूमिका की भी होगी जांच

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: अनधिकृत निर्माण व अतिक्रमण में अधिकारियों की लापरवाही पर सख्त नाराजगी व्यक्त कर हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि कार्रवाई करने में अधिकारियों की विफलता से अराजकता फैलेगी और व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। कोर्ट ने कहा कि संरक्षित स्मारक निजामुद्दीन की बावली व बाराखंभा मकबरे में अनधिकृत निर्माण रोकने में अधिकारियों की नाकामी से हम हैरान हैं। कोर्ट ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) व अन्य प्राधिकरणों द्वारा प्रमाणित किसी भी स्मारक को संरक्षित किया जाएगा, लेकिन अनधिकृत निर्माण को कोई सुरक्षा नहीं मिल सकती है।

हाई कोर्ट गैरसरकारी संगठन जामिया अरबिया निजामिया वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में दावा किया गया है कि बावली गेट के पास खसरा संख्या 556 जियारत गेस्टहाउस, पुलिस बूथ के पास हजरत निजामुद्दीन दरगाह में अवैध और अनधिकृत निर्माण किया गया है। वन भूमि के अंदर अनधिकृत अतिक्रमण और निर्माण पर चिंता व्यक्त करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोर्ट ने मामले में सीबीआइ से जांच कराने का आदेश देने का संकेत देते हुए कहा कि किसी भी संस्था या प्राधिकरण का इस्तेमाल अवैधता को कायम रखने के लिए नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि एक बार हम जांच को सीबीआइ को सौंप देंगे तो दिल्ली पुलिस की भूमिका की भी जांच की जाएगी। हर किसी की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। यह कई एजेंसियों की विफलता है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले इन कई अधिकारियों ने हमें निराश किया है। यह है चौंकाने वाला है।

कोर्ट ने कहा कि पहले से ही सील किए गए गेस्टहाउस की तीन ऊपरी मंजिलों पर हुए अवैध निर्माण पर न तो एमसीडी और न ही डीडीए ने अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की। यह निर्माण पहले ही डीडीए की भूमि पर अतिक्रमण करके किया गया था। सुनवाई के दौरान निर्माण करने वाले संपत्ति के मालिक ने कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए समय देने की मांग की। उसने संपत्ति हासिल करने के संबंध में दस्तावेज पेश करने की बात की। अदालत ने जब पूछा कि संपत्ति पहले ही सील होने के बावजूद तीन मंजिलों पर निर्माण कैसे किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि इस सवालों का जवाब जानने के लिए हम जांच के लिए सीबीआइ को लाना चाहते हैं। हम किसी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करना चाहते हैं। यह टिप्पणी करते हुए अदालत ने मामले की सुनवाई 13 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी।

अदालत ने कहा कि अधिकारियों द्वारा संरक्षित स्मारकों के रूप में प्रमाणित स्मारकों को छोड़कर वन भूमि के अंदर किसी अन्य निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुनवाई के दौरान डीडीए व अन्य प्राधिकरणों की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने अदालत को सूचित किया कि किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय विरासत के हिस्से के रूप में घोषित सभी संरचनाओं को संरक्षित किया जाएगा।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण

'दिल्ली के विकास में डीडीए की बड़ी भूमिका'

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि दिल्ली के विकास में डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) की बड़ी भूमिका है। राजधानी के सुंदरीकरण को लेकर प्राधिकरण प्रतिबद्ध है। उपराज्यपाल, दक्षिणी दिल्ली सांसद रमेश बिधूड़ी और श्रीनिवासपुरी के पार्षद राजपाल सिंह ने बृहस्पतिवार को नेहरू प्लेस में स्काईवाक और नवीनीकरण कार्यों का उद्घाटन किया।

वीके सक्सेना

राज्यपाल ने कहा कि नेहरू प्लेस में बनाए गए स्काईवाक और अन्य कार्यों में करीब 75 करोड़ रुपये की लागत आई है। यह स्काईवाक शहर की सुंदरता को बढ़ाएगा। उपराज्यपाल ने कहा कि डीडीए न केवल शहरी क्षेत्रों के उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी में उपेक्षित गांवों के विकास के लिए भी काम कर रहा है। इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में 300 और अगले वर्ष 600 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। उन्होंने नेहरू प्लेस मार्केट एसोसिएशन के सदस्यों से क्षेत्र की स्वच्छता और रखरखाव पर विशेष जोर देने के लिए कहा।

राज्यपाल ने कहा कि आने वाले दिनों में डीडीए की कई ऐसी परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं, जिन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इस मौके पर डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा और आल नेहरू प्लेस डवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।

NAME C THE INDIAN EXPRESS, FRIDAY, FEBRUARY 9, 2024

'GREEN AREAS ARE LUNGS OF CITY'

HC disposes of plea to stop demolition, says no illegal structure on public land

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, FEBRUARY 8

"RIGHT TO health, right to breathe, and right to heritage and culture have to be harmonised and balanced," said the Delhi High Court on Thursday, while hearing a public interest litigation (PIL), seeking directions to authorities including the Delhi Development Authority (DDA) to desist from demolishing the 'Ashiq Allah Dargah', including the 'Baba Farid' chillagah and other nearby historical monuments, in Mehrauli or Sanjay Van.

A division bench of Acting Chief Justice Manmohan and Justice Manmeet Pritam Singh Arora said in the order, "This Court is of the view that undoubtedly life in its expanded horizons includes all that gives meaning to a man's life, including his culture and heritage, and the protection of that heritage in its full measure. However, this Court takes judicial notice of the fact that Delhi is one of the cities that are worst affected by pollution..." It said Mehrauli and Sanjay Van are marked as "green/forest areas" in the city's Master Plan, adding that green areas are the "lungs of the city", and all statutory authorities have to put in efforts to ensure that "no illegal or unauthorised construction is carried out on this public land".

The HC, after examining photos in PIL, said that it was apparent that some of the structures located in the midst of thick forest have been "renovated recently, and are occupied by certain families".

The petitioners' counsel argued that the area where the Ashiq Allah Dargah is, has been barricaded by police as well as public access has been restricted..., raising "serious apprehension of its impending demolition". He argued "the dargahs and surrounding monuments ought to be protected".

Authorities working at ground level, all failed us: Delhi HC

New Delhi: The Delhi High Court on Thursday said that despite "multi-disciplinary jurisdiction" of the city's civic authorities, it is troubled over their failure to prevent "unauthorised construction" at a sealed property near centrally protected monuments Nizamuddin ki Baoli and Barakhamba Tomb.

The HC was hearing a public interest litigation (PIL) moved by an NGO, Jamia Arabia Nizamia Welfare Education Society, claiming that "illegal and unauthorised construction" is underway at 'Khasra number 556 Ziyarat guest house' near the baoli (stepwell).

During the hearing, a division bench of Acting Chief Justice Manmohan and Justice Manmeet Pritam Singh Arora said, "We are troubled by the fact that the DDA, MCD, Delhi Police, and ASI have all not risen to the occasion. With so many authorities working at the ground level, they have all failed us... We will bring in an independent investigative agency and it will examine it." **ENS**

FULL REPORT ON
www.indianexpress.com

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, FEBRUARY 9, 2024

HC hints at CBI probe into illegal construction

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Delhi High Court on Thursday lamented the failure of multiple authorities in curbing unauthorised construction, saying this would lead to "complete lawlessness" in the city and the entire system would collapse.

A bench of acting Chief Justice Manmohan and Justice Manmeet PS Arora also hinted at ordering a CBI probe to investigate lapses by all authorities in stopping unauthorised construction near centrally-protected monuments Nizamuddin ki Baoli and Barakhamba Tomb.

"Once we transfer the investigation to CBI, the role of Delhi Police will also be examined. Everyone's responsibility should be fixed. It is a failure of multiple agencies. These multiple authorities working on the ground level have all failed us. This is shocking," the bench told the counsels for Municipal Corporation of Delhi (MCD), Delhi Development Authority (DDA) and Archaeological Survey of India (ASI).

It added that if such brazen construction "in the heart of Delhi" was allowed, there would be complete lawlessness in the city and everything would collapse.

The court was hearing a public interest litigation filed by NGO Jamia Arabia Nizamia Welfare Education Society, claiming that "illegal and unauthorised construction" was being carried out at a guesthouse near the Baoli gate, Hazrat Nizamuddin Dargah, near police booth".

HC noted that neither MCD nor DDA acted against the unauthorised construction, which was stated to have taken place on the three upper floors of an already-sealed guesthouse illegally built on DDA land near the monuments.

It had earlier said encroachment on public land was like dacoity and asked MCD to use technology, such as drones and satellite images, to maintain vigil.

Expressing displeasure over the unauthorised construction, the court had said there was "serious dereliction of duty" on the part of officials who did not work on the ground in spite of intimation by police and ASI.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली ।
शुक्रवार, 9 फरवरी 2024

NAME OF NEWSPAPERS-------------------------------- Hindustan Times

छतरपुर जोहड़ का अक्टूबर में पूरा होना था काम, अभी 30% ही हुआ

बाउंड्री दोबारा बनाने और खूबसूरती बढ़ाने के काम लगातार पिछड़ रहे

■ राम त्रिपाठी, असोला

छतरपुर क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए जोहड़ (पुराना तालाब) की बाउंड्री दोबारा बनाने और सौंदर्यीकरण के काम लगातार पिछड़ रहे हैं। हालत यह है कि डीडीए के आला अधिकारी भी जिस जोहड़ के दोबारा बनाने के काम का शिलान्यास करते हैं, वो काम भी कई महीने की देर के बाद भी मुश्किल से 30 फीसदी ही पूरा हो पाया है। गांव असोला के जोहड़ को बनाने का काम उसका प्रमाण है।

जोहड़ निर्माण कार्य में लगे डीडीए के दस्तावेजों के अनुसार, पिछले साल 15 मार्च को डीडीए ने असोला गांव के जोहड़ की योजना (NIT) जारी की थी। उसमें जोहड़ के दोबारा बनाने के खर्च का अनुमान 55,99,964 रुपये बताया गया है। काम करने वाली एजेंसी को 1,11,999 रुपये के अग्रिम भुगतान का भी प्रावधान है। यह काम पिछले साल 11 जून को शुरू हो गया था। उस दिन बाकायदा शिलान्यास समारोह भी हुआ था। डीडीए के तत्कालीन चीफ इंजीनियर ने रिबन काटा था। डीडीए के नोटिस के मुताबिक काम 120 दिन में पूरा करना था। यानी अक्टूबर तक काम पूरा करना था। मगर ऐसा नहीं हुआ है।

लोग बोले, कई बार मांग उठाई, पर काम की रफ्तार सुस्त

- पिछले साल 11 जून को शुरू हो गया था काम
- 120 दिन में काम पूरा करने का समय दिया गया था
- जोहड़ के पानी को साफ करना, हरियाली बढ़ाना, लाइट की व्यवस्था करना, वॉकिंग ट्रैक बनाने समेत कई काम हैं बाकी

निवासी ऋषिपाल महाशय ने बताया कि जोहड़ की बाउंड्री वॉल का काम ही पूरा नहीं हो पाया है। बाउंड्री बनाकर जोहड़ के पानी को साफ करना, हरियाली को बढ़ाना, लाइट की व्यवस्था करना, वॉकिंग ट्रैक और लोगों को बैठने के लिए जगह बनाना आदि काम अभी बचा ही हुआ है। जोहड़ के सुस्त काम से दुखी होकर स्थानीय सांसद ने एलजी से लेकर डीडीए उपाध्यक्ष को पत्र लिखे हैं। इसके बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।

लोगों का कहना है कि गांव बामनोली जोहड़ की स्थिति सुधारने का काम भी किया जाना है। पिछले साल ही डीडीए अधिकारी उस जगह का दौरा कर चुके हैं, लेकिन योजना का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है।

Delhi has sufficient shrines, imperative to save forests: HC

Shruti Kakkar
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi high court on Thursday refused to entertain a plea seeking protection against demolition of two religious structures in Sanjay Van, saying that the Capital "already had sufficient dargahs and temples" and it was now imperative to restore the forest.

The two structures in question are the Ashiq Allah dargah, and the chillagah of Baba Farid. The petitioner, Himanshu Damle, a promoter of Delhi's history, contended that there was apprehension regarding the demolition of the structures as police had barricaded the area, restricted its access, and removed the caretakers of the dargah.

The plea said that the "complex structure could be destroyed overnight by the Delhi Development Authority (DDA) which demolished adjacent structures including the Akhunji Masjid and the Haji Rozbih Dargah, as well as certain 12th-century graves without notice".

However, the court was of the view that the removal of unauthorised constructions, including unprotected religious structures, from the forest land is for the betterment of the society at large.

"We cannot even breathe in Delhi... Let the forest be restored. These (Sanjay Van) are green lungs, people are dying in the city due to pollution. This is our last bastion. Enough peers, dargah and temples are there in the city," a bench led by acting chief justice Manmohan said to advocate Satyajit Sarna, who appeared for Damle.

The court added that green areas are the lungs of the city and efforts have to be made by all statutory authorities to ensure that no illegal and unauthorised construction is carried out on public land.

The DDA lawyer submitted that the green area in Sanjay Van was completely encroached upon and the civic authority had also demolished various structures, including four temples.

During the hearing, the bench, also comprising justice Manmeet Pritam Singh Arora, said that health needs to be a priority. "We have such an unhealthy population today. Health is the priority. Green environment is the priority otherwise you won't be able to exist," the court said.

Disposing of the plea, the bench said that DDA and the Union ministry of housing and urban affairs have issued statements saying they would not demolish structures declared as a part of national heritage or ones that are deemed to be protected by a statutory authority.

To be sure, the 13th-century dargah is an unprotected monument and finds a mention in the "List of Muhammadan and Hindu Monuments, Volume III Mahrauli Zila" published in 1922 by Maulvi Zafar Hasan, assistant superintendent of the Archaeological Survey of India (ASI).

According to the National Mission on Monuments and Antiquities, the site is a "living monument", meaning it continues to be used for religious purposes.

The court, in a related development earlier this week, had directed DDA to maintain the status quo in the Mehrauli area on which the 600-year-old Akhunji Masjid was demolished, till February 12. A bench of justice Sachin Datta, however, clarified that its order would not preclude the civic authority from acting against other illegal properties in the area.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPER नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शुक्रवार, 9 फरवरी 2024 ATED

स्काईवॉक से आपस में जुड़ गए नेहरू प्लेस मार्केट और मेट्रो स्टेशन

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

नेहरू प्लेस कमर्शल मार्केट और नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन जाने के लिए लोगों को सड़क क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। यह दोनों स्काईवॉक के जरिए आपस में जुड़ गई है। इससे लोगों को मार्केट से मेट्रो स्टेशन जाने में सुविधा होगी। एलजी वीके सक्सेना ने गुरुवार को इस स्काईवॉक का उद्घाटन किया। यह स्काईवॉक नेहरू प्लेस के अपग्रेडेशन वर्क का हिस्सा है।

डीडीए से मिली जानकारी के अनुसार 75 करोड़ की लागत से इस प्रोजक्ट को 4 साल में पूरा किया गया है। उद्घाटन समारोह में साउथ दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी, डीडीए के वाइस चेयरमैन सुभाषिश पांडा भी मौजूद रहे। लंबे समय से चल रहे इस प्रोजेक्ट को एलजी वीके सक्सेना के दखल के बाद मई 2022 में रफ्तार मिली।

इससे लोगों को मार्केट से मेट्रो स्टेशन जाने में सुविधा होगी

एलजी ने इस मौके पर कहा कि डीडीए अर्बन एरिया को अपग्रेड करने के अपने वादे पर कायम है। इसके साथ ही डीडीए ने दिल्ली उपेक्षित रहे गांवों के विकास का जिम्मा भी उठाया है। यह स्काईवॉक काफी शानदार बना है और इससे इस पूरे एरिया की खूबसूरती बढ़ी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह इसे मेंटेन रखें। लोगों के सपोर्ट के बिना कोई भी प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सकता है। उन्होंने नेहरू प्लेस मार्केट असोसिएशन के लोगों से अपील की कि वह इस एरिया की सफाई का खयाल रखें और इसे मेंटेन रखें।

स्मार्ट लाइट पोल सिस्टम

नेहरू प्लेस मार्केट को आकर्षक लुक देने के साथ यहां कई तरह की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। यहां पर वाई-फाई सुविधा के साथ स्मार्ट लाइट पोल सिस्टम, स्पीकर सिस्टम, सीसीटीवी सिस्टम, एम्फिथिएटर, एलईडी स्क्रीन वॉल, टैंसिल शेडिंग स्ट्रक्चर आदि की सुविधा दी गई है। साथ ही सीवेज सिस्टम को पूरी तरह बदला गया है। छह मीटर चौड़ा यह स्काईवॉक नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन को प्लाजा से जोड़ रहा है। इस स्काईवॉक में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा भी है। साथ ही यहां दिव्यांगों के लिए रैंप सुविधा भी है। लोगों की सुविधा के लिए यहां नए फुटपाथ और टॉइलट ब्लॉक भी बनाए गए हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए अधिकांश फंड डीडीए को मिनिस्ट्री से मिला।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FRIDAY, FEBRUARY 9, 2024

Nehru Palace! Swanky skywalk makes approach to market from metro station safer and a feast for eyes

Photos: Rajesh Mehta

Siddhanta.Mishra
@timesgroup.com

New Delhi: Lieutenant governor VK Saxena inaugurated the Nehru Place skywalk, which links the market with the Delhi Metro station, on Thursday. With the skywalk, planned five years ago, open now, people don't need to climb down from the elevated station and cross the busy Astha Kunj Road to reach Nehru Place District Centre.

"The skywalk is appealing and it will add to the beauty of the city. In the days to come, DDA will complete many such projects," said Saxena.

The market sees heavy pedestrian movement and the congested main road is risky for them. "I am very happy that the skywalk has been opened. This will be a great help for me to reach my college," said Ramanujan College student Diya. "I now exit the metro station and use the skywalk instead of crossing the dangerous road like earlier."

The skywalk followed the revamp of the market. In December 2019, DDA, after receiving a no-objection certificate from the erstwhile South Delhi Municipal Corporation, redevelopment began to achieve uniformity in colour, better fireproofing and illumination. The complex revamp included improving the building facades and drainage and sewerage, upgrading the public plaza by installing tiles and new seating and overhauling the rickety staircases.

"The skywalk is a great step, it is completely integrated with the metro station. So, people can just exit the metro and take the skywalk to reach the market," said a happy Inder Kohli, coordinator, Nehru Place Welfare Association. "The revamp of the district centre has been carried out and it has boosted the firefighting infrastructure. The only things that still need to be better managed are the drainage system and food vendors in and around Nehru Place."

The buildings have been painted white and given proper name boards while the cables have been removed and relocated underground. For people to sit and enjoy, DDA has created an amphitheatre with a large LED screen.

Soon after its opening, the skywalk was being used by people exiting the Nehru Place metro station and going to the district centre and nearby areas. Nehru Place is one of the largest commercial centres in Asia for the sale and purchase of computers and accessories. It was also once a textile hub. Thousands of people, therefore, visit the market every day. However, since the district centre was constructed a long while ago, it required upgradation, which has now been done.

EASE OF ACCESS

Features of skywalk

6 metres
Width

Has both the options of **lift and escalator**

Connecting metro station to Nehru Place centre

LED screen on the skywalk shows air quality

Cost of the entire revamp
₹75 crore

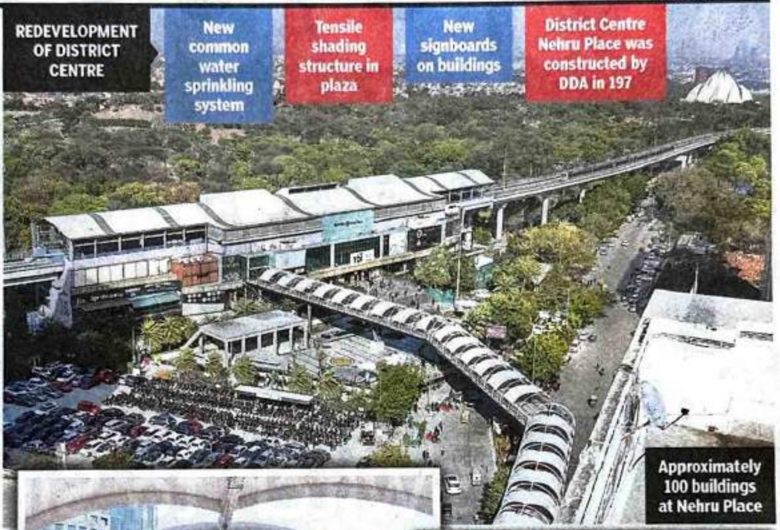

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS Hindustan Times नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2024

Skywalk connecting Nehru Place, Metro station opens

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Lieutenant governor (LG) VK Saxena on Thursday inaugurated a skywalk connecting Nehru Place Metro station and Market Plaza, and other associated infrastructure upgradation work in the Nehru Place market.

The project, which took over four years to be completed at a cost of ₹75 crore, includes the upgradation of the plaza, and building corridors, parking areas, staircases and stormwater drains along with new firefighting system in the entire complex, officials of the Delhi Development Authority (DDA) aware of the development said.

With the skywalk, people will no longer have to climb down from the elevated station and cross the busy Astha Kunj Road to reach the Nehru Place district centre.

The project was completed in over four years at a cost of ₹75 cr. HT

The LG, who is the head of DDA, which executed the project, said that the body was committed to the upgradation of the urban areas along with undertaking development work for the neglected villages.

"We compliment DDA for the upgradation work undertaken at Nehru Place. The skywalk is appealing and it will add to the beauty of the city," the LG said.

Saxena added that the people should also cooperate in the maintenance of the infrastructure. "No project can be successful without support of the public. Nehru Place Market Association members should give special emphasis on the hygiene and maintenance of the area," he said.

The LG later posted on X: "A DDA project worth ₹75 crore, the upgradation works have altered the kerbs, footpaths and facade of the iconic market. The Skywalk will ensure safety of pedestrians & seamless commute, apart from effecting ease of doing business."

South Delhi MP Ramesh Bidhuri and DDA vice-chairman Subhasish Panda were present at the inaugural event.

There is a ramp for differently abled people in the structure, a DDA official said.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

ुक्रवार • 9 फरवरी • 2024 राष्ट्रीय सहारा www.rashtriyasahara.com

जंगल दिल्ली के 'हरित फेफड़े' हैं, उन्हें 'बहाल' किया जाना चाहिए : हाईकोर्ट

नई दिल्ली (एसएनबी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि जंगल दिल्ली के 'हरित फेफड़े' हैं और प्रदूषण से एकमात्र रक्षक हैं और इसलिए उन्हें 'बहाल' किया जाना चाहिए। अदालत ने धार्मिक संरचनाओं के नाम पर अतिक्रमण समेत अनधिकृत निर्माण पर चिंता जताते हुए यह बात कही। उसने कहा कि शहर में पर्याप्त धार्मिक संरचनाएं हैं जहां लोग अपनी श्रद्धा अर्पित कर सकते हैं। इससे जंगलों को कम से कम छोड़ देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि वायु प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यही एकमात्र हमारा रक्षक है। जंगलों को बहाल कर दिया जाए, यही एक सहारा है। आप नहीं समझते, जब आप सांस नहीं ले पाएंगे तो आप क्या देखेंगे और विरासत का आनंद कैसे उठा पाएंगे। हमें अपने हितों को संतुलित करना होगा। पीठ ने कहा कि शहर में पर्याप्त पीर, दरगाह और मंदिर हैं।

डीडीए के वकील ने कहा कि संजय वन के हरित क्षेत्र पर पूरी तरह से अतिक्रमण कर लिया गया है और प्राधिकरण ने चार मंदिरों सहित विभिन्न संरचनाओं को तोड़ दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों से भी कहा कि वे उन लोगों से अनुरोध करें जो जंगल के अंदर रह रहे हैं या जिनके पास मंदिर और गुरुद्वारे हैं। वे परिसर से बाहर निकल जाएं, यह कहते हुए कि यह उनकी भलाई के लिए है। इसी के साथ कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। अगर एएसआई कहेगा कि कोई ढांचा पवित्र है तो अदालत उसे संरक्षित करने का निर्देश देगी, लेकिन कोई वहां नहीं रह सकता, अन्यथा पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने यह टिप्पणी दो याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए की जिसमें प्राचीन स्मारकों एवं महरौली के आशिक अल्लाह दरगाह को तोड़ने से बचाने की मांग की गई थी। पीठ ने टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) या राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से संरक्षित किसी भी स्मारक को नहीं तोड़ा जाएगा, लेकिन अनधिकृत निर्माण को कोई सुरक्षा नहीं मिल सकती। पीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा जो विरासत के रूप में घोषित किया गया हो। इससे हमारा कोई झगड़ा नहीं है।

संजय वन के हरित क्षेत्र पर पूरी तरह से अतिक्रमण कर लिया गया है : डीडीए

प्राधिकरण ने चार मंदिरों सहित विभिन्न संरचनाओं को तोड़ा

एएसआई या राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण से संरक्षित किसी भी स्मारक को नहीं तोड़ा जाएगा : हाईकोर्ट

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी DELHI

amarujala.com

शुक्रवार, 9 फरवरी 2024 NEWSPAPERS---

नेहरू प्लेस कॉमर्शियल मार्केट और मेट्रो स्टेशन स्काईवॉक से जुड़े

नई दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बृहस्पतिवार को नेहरू प्लेस में नवनिर्मित स्काईवॉक का उद्घाटन किया। यह परियोजना 75 करोड़ रुपये की लागत से चार वर्ष में पूरी हुई। इस परियोजना के तहत नेहरू प्लेस कामर्शियल मार्केट व नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन जुड़ गए है। यह स्काईवॉक छह मीटर चौड़ा है। इस दौरान रमेश बिधूड़ी, डीडीए के उपाध्यक्ष शुभाषीस पांडा उपस्थित थे।

इस मौके पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि डीडीए शहरी क्षेत्र का विकास ही नहीं, बल्कि उपेक्षित गांवों में भी विकास कार्य कर रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि स्काईवॉक आकर्षक है और यह शहर की सुंदरता को बढ़ाएगा। उन्होंने लोगों से इसके रखरखाव में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि कोई भी परियोजना जनता के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती। ब्यूरो

अनधिकृत निर्माण रोकने में अफसरों की विफलता पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

कहा, शहर में अराजकता फैल जाएगी और व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को अनधिकृत निर्माण पर अंकुश लगाने में प्राधिकरणों की विफलता पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि इससे शहर में पूरी तरह अराजकता फैल जाएगी और पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। अदालत ने मामले की सीबीआई जांच का संकेत देते हुए दिल्ली पुलिस सहित सभी संबंधित एजेंसियों की भूमिका की जांच करवाने को कहा है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि केंद्र संरक्षित स्मारकों निज़ामुद्दीन की बावली और बाराखंभा मकबरे के पास अनधिकृत निर्माण को रोकने में अधिकारियों की विफलता ने अदालत को चौंका दिया है।

अदालत ने मामले में सीबीआई जांच का आदेश देने का संकेत देते हुए कहा कि किसी भी संस्था या प्राधिकरण का इस्तेमाल अवैधता को कायम रखने के लिए नहीं किया जा सकता है। एक बार जब हम जांच को सीबीआई को स्थानांतरित कर देंगे, तो दिल्ली पुलिस की भूमिका की भी

सीबीआई जांच के दिए संकेत कहा, सभी की भूमिका की जांच कर जिम्मेदारी तय की जाएगी

जांच की जाएगी। सबकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, यह कई एजेंसियों की विफलता है।

अदालत एनजीओ जामिया अरबिया निज़ामिया वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की ओर से दायर एक जनहित याचिका मामले पर सुनवाई कर रही है जिसमें दावा किया गया था कि खसरा नंबर 556, जियारत गेस्टहाउस, बावली गेट, हजरत निज़ामुद्दीन दरगाह स्थित पुलिस बूथ के पास अवैध और अनधिकृत निर्माण किया जा रहा है।

अदालत ने कहा कि न तो दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और न ही दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जो पहले से ही सील किए गए गेस्टहाउस की तीन ऊपरी मंजिलों पर स्मारकों के पास डीडीए की जमीन पर हुआ है, जो अवैध रूप से बनाया गया है।

अब संपत्ति के मालिक ने मुख्य याचिका में एक आवेदन दायर किया है, जिसमें यह दिखाने के लिए कुछ दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति मांगी गई है कि उसने संपत्ति कैसे हासिल की।

पूछा-सील संपत्ति पर निर्माण कैसे किया जा सकता है

पीठ ने पूछा कि जब संपत्ति पहले ही सील कर दी गई थी तो तीन मंजिलों पर निर्माण कैसे किया जा सकता है और कहा कि इसीलिए हम जांच सीबीआई को सौंपना चाहते हैं। हम किसी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करना चाहते। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी तय की है। पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान कहा था कि सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण डकैती के समान है और एमसीडी से निगरानी बनाए रखने के लिए ड्रोन और उपग्रह छवियों जैसी तकनीक का उपयोग करने को कहा था। अदालत ने अनधिकृत निर्माण पर नाराजगी व्यक्त की थी और कहा था कि पुलिस और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की सूचना के बावजूद जमीन पर काम नहीं करने वाले अधिकारियों की ओर से कर्तव्य में गंभीर लापरवाही हुई है।

एलजी वी के सक्सेना ने नेहरू प्लेस में 6 मीटर चौड़े स्काईवॉक का किया उद्घाटन

परियोजना सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती: एलजी

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): आधुनिक सुविधाओं और राष्ट्रीय राजधानी के सौंदर्यीकरण की प्रतिबद्धता को पूरा करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वी के सक्सेना ने गुरुवार को नेहरू प्लेस के उन्नयन कार्य के साथ-साथ नवनिर्मित स्काईवॉक का उद्घाटन किया। यह परियोजना 75 करोड़ रुपए की लागत से 4 वर्ष की समयावधि में पूरी की गई है। इस अवसर पर दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा के अलावा दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी उपस्थित रहे। उपराज्यपाल सक्सेना ने इस मौके पर कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण सिर्फ शहरी क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय राजधानी में उपेक्षित गांव के विकास हेतु कार्य भी कर रहा है। एलजी ने नेहरू प्लेस में किए गए उन्नयन कार्य के लिए डीडीए की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्काईवॉक आकर्षक है और

यह शहर की सुंदरता को बढ़ाएगा। उन्होंने लोगों से इसके रख-रखाव में सहयोग करने का आग्रह किया और कहा कि कोई भी परियोजना जनता के सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकती। उन्होंने नेहरू प्लेस मार्केट एसोसिएशन के सदस्यों से क्षेत्र की स्वच्छता और रख-रखाव पर भी विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। सभा को संबोधित करते हुए एलजी ने विश्वास दिलाया कि आने वाले दिनों में डीडीए की अनेक ऐसी परियोजनाएं क्रम में हैं, जिन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना में प्लाजा का उन्नयन, कॉरिडोरों का निर्माण, पार्किंग एरिया, सीढ़ियां और बरसाती जल निकासी शामिल हैं। इसके अलावा, सौंदर्यपरक दृश्य में वृद्धि के लिए यहां वाई-फाई वाले स्मार्ट लाइट पोल, स्पीकर सिस्टम और सीसीटीवी सिस्टम, एम्फीथिएटर और एलईडी स्क्रीन वॉल, प्लाजा क्षेत्र में टैंसिल शेडिंग स्ट्रक्चर है।

6 मीटर चौड़े स्काईवॉक का किया गया निर्माण

लिफ्ट और एस्केलेटर के प्रावधान के साथ नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन को प्लाजा से जोड़ने के लिए 6 मीटर चौड़े स्काईवॉक का निर्माण किया गया है। इसके अलावा दिव्यांगों के लिए रैंप की भी सुविधा है। जनता की सुविधा के लिए नए फुटपाथ और टॉयलेट ब्लॉक का भी निर्माण किया गया है। फंडिंग का बड़ा हिस्सा एमओएचयूए, भारत सरकार द्वारा यूडीएफ के माध्यम से डीडीए को प्रदान किया गया था, जो भारत सरकार की ओर से डीडीए द्वारा निर्मित एवं रख-रखाव किया गया एक फंड है। चूंकि, इसका निर्माण बहुत पहले किया गया था, इसलिए नेहरू प्लेस में यात्रियों की आवाजाही की सुगमता के लिए इसे तत्काल अपग्रेडेशन/ रीमॉडलिंग/ फेस लिफ्टिंग की आवश्यकता थी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
NEW DELHI | FRIDAY, 9 FEBRUARY, 2024 PAPERS------ THE HINDU

L–G Saxena inaugurates newly built skywalk at Nehru Place

OUR CORRESPONDENT

Delhi L-G VK Saxena along with other dignitaries during the inauguration of skywalk, in New Delhi, on Thursday

NEW DELHI: The Lieutenant Governor (L-G) of Delhi, V K Saxena inaugurated the newly constructed skywalk connecting Nehru Place commercial market with the Nehru Place Metro Station, on Thursday.

The project was completed within four years, with a cost of Rs 75 crores.

It includes, upgradation of the plaza, building corridors, parking areas, staircases and storm water drains, along with a fire fighting system for the entire complex. Apart from this, there are smart light poles with Wi-Fi, speakers and CCTV systems, amphitheatre, LED screen wall and a complete restructuring of the existing sewage system.

New footpath and toilet block have also been constructed.

The skywalk itself is six metres wide and connects the metro station to the plaza through a lift and an escalator, with a ramp for differently-abled people.

A major portion of the project has been funded by the Ministry of Housing and Urban Affairs through the Urban Development Fund. The latter has been created and maintained by the Delhi Development Authority (DDA) on behalf of the Government of India.

The L-G thanked the authority for their contribution to the project and said, 'DDA was not only committed to up-gradation of the urban areas but also undertaken work for the development of the neglected villages in the National Capital.'

'The skywalk is appealing and it will add to the beauty of the city. In the days to come, many such projects by DDA are in pipeline, which will be done in a time bound manner,' he added, while addressing the event.

Member of Parliament, Ramesh Bidhuri and DDA Vice Chairman Subhasish Panda were also present at the inauguration.

L-G inaugurates new skywalk, market hub at Nehru Place

Lieutenant-Governor V.K. Saxena on Thursday inaugurated a six-metre-wide skywalk and the upgraded Nehru Place market hub here, officials said on Thursday. The entire project was completed in a span of four years at a cost of ₹75 crore by the Delhi Development Authority. The skywalk connects Nehru Place metro station to the plaza, and is equipped with a lift, escalator, and a ramp for persons with disabilities. A new footpath and toilet block has also been built. PTI

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

9 फरवरी • 2024 राष्ट्रीय सहारा

नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन से आवाजाही को आसान बनाने के लिए बृहस्पतिवार को स्काईवॉक का लोकार्पण करते उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना साथ में हैं सांसद रमेश बिधूड़ी व अन्य। फोटो : एसएनबी

मेट्रो स्टेशन से नेहरू प्लेस मार्केट को सीधे जोड़ेगा नया स्काई वॉक

- उपराज्यपाल ने किया स्काई वॉक का लोकार्पण
- मार्केट एसोसिएशन सफाई एवं स्वच्छता पर दे ध्यान : उपराज्यपाल

नई दिल्ली (एसएनबी)। दक्षिणी दिल्ली स्थित नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन से यात्री अब सीधे मार्केट के लिए जा सकेंगे। यात्रियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बृहस्पतिवार को स्काईवॉक का लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नेहरू प्लेस काफी पुरानी मार्केट है। उन्होंने संकेत दिया है कि नेहरू प्लेस की संपत्तियों एवं सुविधाओं का उच्चीकरण किया जाएगा। इसके लिए नेहरू प्लेस मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का भी सहयोग भी मांगा। इस मौके पर स्थानीय सांसद रमेश बिधूड़ी एवं डीडीए उपाध्यक्ष सुभाशीष पांडा समेत अन्य अधिकारी भी थे।

उन्होंने कहा कि नया स्काई वॉक 6 मीटर चौड़ा, लिफ्ट, एस्केलेटर से युक्त है। दिव्यांगों के लिए रैंप की सुविधा है और टॉयलेट ब्लॉक भी बनाया गया है। 75 करोड़ की लागत से चार साल में तैयार हुए इस प्रोजेक्ट की लागत का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार ने डीडीए को मुहैया कराया है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप-राज्यपाल ने कहा कि नेहरू प्लेस मार्केट के उन्नयन लेकर कई योजनाएं पाइप लाइन में हैं। इसमें वाई-फाई, स्पीकर प्रणाली, सीसीटीवी, एम्फीथिएटर समेत अन्य योजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि नेहरू प्लेस मार्केट को डिस्ट्रिक्ट सेंटर के रूप में बनाया गया था आज वह एशिया की सबसे बड़ा कंप्यूटर बाजार बन गया है। यहां रोजाना हजारों की संख्या में लोग आते हैं। इसको देखते हुए तत्काल अपग्रेडेशन, रीमॉडलिंग , फेस लिफ्टिंग की जरूरत है। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से बाजार की स्वच्छता एवं रख-रखाव पर ध्यान देने का आग्रह किया।

the pioneer
DELHI I FRIDAY I FEBRUARY 9, 2024

Newly constructed skywalk inaugurated

STAFF REPORTER ■ NEW DELHI

Giving a boost to the beautification drive of the national capital with modern facilities and infrastructure, Delhi Lt Governor (LG) VK Saxena on Thursday here inaugurated the newly constructed skywalk along with the upgradation work of Nehru Place.

The entire project was completed in a time span of 4 years at a cost of Rs 75 crore. Ramesh Bidhuri, MP South Delhi and Subhasish Panda, Vice Chairman Delhi Development Authority(DDA), were also present at the inaugural event.

Addressing the gathering, Saxena said the DDA was not only committed to upgradation of the urban areas but also undertaken work for the development of the neglected villages in the National Capital.

He complimented the DDA for the upgradation work undertaken at Nehru Place. "The skywalk is appealing and it will add to the beauty of the city," the LG said.

He urged people to co-operate in its maintenance, adding that no project can be successful without support of the public. He also asked the Nehru Place Market Association members to give special emphasis on the hygiene and maintenance of the area.